निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों का निरीक्षण

सफाई का कार्य नियमित रूप से करवाने व भुट्टा बाजार में लगी अवैध गुमटी को हटाने के दिये निर्देश

रतलाम (तेज एक्सप्रेस)। शहर के व्यवस्था का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कर व्यावसायिक क्षेत्र व मुख्य मार्गो की सफाई के साथ ही नाले नालियों की सफाई के निर्देष संबंधितों को देने के साथ ही भुट्टा बाजार में लगी अवैध गुमटी को हटाने के निर्देष भी दिये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दो बत्ती, सैलाना बस स्टैण्ड, गीता मंदिर रोड, भुट्टा व्यावसायिक व अन्य क्षेत्रों की सफाई बाजार, डालू मोदी बाजार, नाहरपुरा, चांदनी चौक, नौलाईपुरा, धानमण्डी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर नाले नालियों की सफाई के निर्देश संबंधित को देते हुए नौलाईपुरा क्षेत्र के नाले की सफाई का कार्य तत्काल प्रारंभ करवाने के निर्देष दिये।

निरीक्षण के दौरान उन्होने अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये कि षहर के सभी सार्वजनिक शौचालय व यूरिनल की नियमित रूप से सफाई करवाई जाये सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी इस हेतु सभी पुरी निश्ठा, लगन एवं ईमानदारी से कार्य करे।

तेज एक्सप्रेस

19-4-22

स्वच्छता में उच्चतम रेटिंग के प्रयास करें नगरीय निकाय : मुख्यमंत्री श्री चौहान

19-4

वित्त आयोग की 931.50 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित

भोपाल । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह

चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के प्रयास करें। नगरीय क्षेत्रों में अधो-संरचना विकास के कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना में और अच्छे परिणाम लाने के प्रयास करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की वित्त वर्ष 2021-22 की 931 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को सिंगल क्लिक से जारी करते हुए यह बात कही। आज प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों को 432 करोड़ 50 लाख रूपए और नॉन मिलियन प्लस नगरों को 499 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व वसूली में अधिकांश शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष निकायों ने गत वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त किया है। इसके लिए निकाय बधाई के पात्र हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरीय विकास विभाग शहरों को बदलने के सद्प्रयासों में संलग्न है। नगरीय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रदेश में दो श्रेणियों के नगर हैं। प्रथम श्रेणी मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। मिलियन प्लस शहरों को अनुदान मिलने से वायु गुणवत्ता में सुधार, पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य बेहतर तरीके से होंगे। नॉन मिलियन शहरों को बेसिक अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग वे विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में उनके गत कार्यकाल में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की गईं। गत 2 वर्ष में भी नगरीय विकास क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अनेक योजनाओं में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। आज जारी की जा रही राशि से प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों के लिए और भी अच्छी सुविधाएँ विकसित करने का कार्य होगा। मध्यप्रदेश में नगरों की स्वच्छता के कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड प्राप्त कर रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल-संरक्षण के कार्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने प्रदेश में माफिया पर प्रभावी नियंत्रण के कदम उठाए हैं। अतिक्रमित भूमि मुक्त करवाई जा रही है, जो गरीबों के मकानों के लिए आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में हमारे शहर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं प्रशासन श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, आयुक्त नगरीय विकास एवं प्रशासन श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले भी वर्चुअली जुड़े।

किस कार्य के लिए कितनी राशि मिली

मिलियन प्लस नगरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 131 करोड़ 50 लाख और पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता के लिए 301 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। नॉन मिलियन नगरों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 199 करोड़ 60 लाख और स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल और संरक्षण के लिए 299 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। प्रयास करें कि हितग्राहियों को समय से किश्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

ग्रीष्म ऋतु में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि किसी जिले में पेयजल संकट न हो। इसके लिए आवश्यक तैयारियाँ की जाएँ। मानसून आगमन से पहले सड़कों में आवश्यक सुधार करें।

प्रदेश के सभी शहरों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अर्बन क्षेत्र के जिन स्ट्रीट वेंडर्स (शहरी पथ विक्रताओं) ने 10 हजार रूपए का ऋण चुकता कर दिया है, उन्हें अब 20 हजार रूपए का ऋण लेने के लिए प्रेरित करें।

19-4-22

ईद को लेकर तैयारी शुरू,पुरानी ईदगाह पर करवाई साफ-सफाई

रतलाम। रविवार को पुरानी ईदगाह का साफ सफाई व निरीक्षण किया गया। पिछले 2 वर्षों के बाद ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी। जिसकी तैयारियों को लेकर समाज सेवियो के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष यास्मिन शेरानी, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि शहजाद खान, शाहिद हुसैन, नासिर भाई अख्तर भाई अनीस खान ने पुरानी ईदगाह का निरीक्षण किया व सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यास्मीन शेरानी ने बताया कि ईदगाह में 2 साल से नमाज नहीं होने की वजह से रखरखाव नहीं हो पाया था साथ ही यहां पर कई प्रकार की अव्यवस्था भी व्याप्त थी उसको जल्द ही निराकरण किया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम सहा.स्वा.अधिकारी ए पी सिंह व कर्मचारी भी मौजूद रहे।

19-4-22

समाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत असंगठित श्रमिको के सम्मेलन का आयोजन

रतलाम। सम्पूर्ण भारत मे भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़े का आयोजन 7 से 20 अप्रेल तक किया जा रहा है। इसी तारतम्य मैं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम के जिला प्रभारी इब्राहिम शैरानी, कार्यक्रम संयोजक एवं जिला अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंसूर जमादार, सह संयोजक एवं जिला मीडिया प्रभारी मुबारिक शैरानी द्वारा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान मैं असंगठित श्रमिको के सम्मेलन का आयोजन कर वेंडिंग नेम प्लेट एवं प्रधानमंत्री के संदेश को अतिथियों के द्वारा वितरित कराया गया। कार्यक्रम मे भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक पोरवाल, जिला महामंत्री निर्मल कटारिया, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष इब्राहिम शैरानी, जुग्गी झोपड़ी प्रदेश संयोजिका अनिता कटारिया, जिला मंत्री सोना शर्मा, जिला भंडार प्रभारी दशरथ पाटीदार, मण्डल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, मण्डल महामंत्री राकेश परमार, धर्मेंद्र सिंह, महिला मोर्चा जिला महामंत्री महिला मोर्चा अनिता पाहुजा मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री प्रो इमरान हुसैन द्वारा एवं आभार जिला मीडिया प्रभार मुबारिक शैरानी द्वारा माना गया। इस

अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बबलू पटेल, वाजिद खान, रईस कुरेशी, सलीम नेताजी, हमीद खान, लतीफ बा, शेख अजरुद्दीन, ज़ाकिर हुसैन फक्का, अजहर मंसूरी, शरीफ कुरेशी, इमरान खान, अकबर कुरेशी आदि अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। उक्त जानकारी में इसरार रेहमानी जिला कार्यालय मंत्री ने दी।

19-4-22

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते हैं, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं, उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 18 अप्रैल सोमवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मनोज जोशी व राज रतन पर 200-200, कालू भाई, पवन चौरसिया, अंकित चौरसिया, शाहनवाज खान, चांद मोहम्मद, इकरार खान, जीवन, गंगाबाई व संतोश कुमार पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही कुलदीप भट्ट, विजय मेल्वा, मनीश झाझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

नगर निगम के विभिन्न करों से 11.68 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम। संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराए गए करों के तहत 18 अप्रैल को कुल राशि रूपए 11,68,630/- का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 18 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय 300067, वसूली दल 141000 कुल 441067, जलकर कार्यालय से 446150, वसूली दल 120800 कुल 566950, स्पॉट फाईन 14000, लायसेंस 1500, दुकान-गुमटी किराया कार्यालय 48556, वसूली दल 10240 कुल 58796 व लीजरेंट 86317 इस तरह कुल राशि रूपए 11,68,630/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

स्वच्छता में सरपट दौड़े शहर, अब सरकार करेगी अफसरों को पुरस्कृत

सीएम ने 15वें वित्त आयोग के 931.50 करोड़ किए ट्रांसफर

भोपाल @ पत्रिका. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के प्रयास करें। राजस्व वसूली में अधिकांश शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस साल निकायों ने बीते साल की तुलना में 35% अधिक राजस्व प्राप्त किया है। यह बात शिवराज ने सोमवार को मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2021-22 की 931.50 करोड़ की राशि निकायों को सिंगल क्लिक से ट्रांसफर करने के मौके पर कही। प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों को 432.50 करोड़ और नॉन मिलियन प्लस नगरों को 499 करोड दिए गए हैं। शिवराज ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले निकायों व अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

पत्रिका 19-4-22

ते नंबर एक पर

कहीं कचरा नहीं उठ रहा, कहीं टूटे डिब्बे

पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट

रतलाम. शहर में कही कई दिन से कचरा नहीं उठ रहा है तो कही कचरा डालने के लिए मोहल्लों में लगे हुए डस्डबिन याने की कचरा डिब्बे ही टूट गए है। इनको न तो बदला जा रहा है नहीं नए लगाए जा रहे है। ऐसे में रहवासी रोड पर कचरा डालने को मजबूर है।

शहर के लोकेंद्र टाकिज रोड पर लगे हुए यह डस्टबिन तीन दिन से टूटे हुए पड़े हुए थे। सोमवार को इनको स्थानीय कारोबारियों द्वारा लगातार शिकायत करने के बाद उठाया तो गया, लेकिन इनके स्थान पर नए डस्टबिन अब तक नहीं लगाए है।

शहर के घांस बाजार, भट्टा बाजार, चौमुखीपुल, चांदनीचौक, दो बत्ती, राममंदिर आदि वो क्षेत्र है जहां कारोबारी इस प्रकार के डस्टबिन की मांग कर रहे है। इसके अभाव में कारोबारियों को कचरा डालने में परेशानी हो रही है। कारोबारियों के अनुसार अगर मैजिक वाहन दो से तीन दिन तक नहीं आए तो उनके दुकान के डस्टबिन में रखा हुआ कचरा बास देने लगता है। इससे परेशानी हो रही है। इसलिए

कारोबारी क्षेत्र में डस्टबिन लगाए जाने की जरुरत है।

सीधे शिकायत करें

कारोबारियों से चर्चा करके उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर मैजिक वाहन समय पर नहीं आता है तो मुझे सीधे मोबाइल नंबर 7471144900 पर संपर्क कर शिकायत की जा सकती है। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

पत्रिका 19-4-22

म रेटिंग के प्रयास करें नगरीय निकाय : शिवराजसिंह चौहान

ए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित ● बीते वर्ष से 35 प्रतिशत अधिक राजस्व पर, नगरीय विकास और आवास विभाग को दी बधाई

जस्व प्राप्त किया है। इसके लिए निकाय बधाई के पात्र
कार्य करने वाले निकायों एवं अधिकारियों को
कया जाएगा।
मंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरीय विकास विभाग
बदलने के सद्प्रयासों में संलग्न है। नगरीय विकास
से चल रहे हैं। प्रदेश में दो श्रेणियों के नगर हैं। प्रथम
नयन प्लस आबादी वाले नगरों की है। प्रदेश में 10
ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में भोपाल, इंदौर,
और ग्वालियर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में 10 लाख से
संख्या वाले शहर शामिल हैं। मिलियन प्लस शहरों को
मिलने से वायु गुणवत्ता में सुधार, पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य बेहतर तरीके से होंगे। नॉन मिलियन शहरों को बेसिक अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग वे विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में उनके गत कार्यकाल में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की गई। गत 2 वर्ष में भी नगरीय विकास क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अनेक योजनाओं में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। आज जारी की जा रही राशि से प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों के लिए और भी अच्छी सुविधाएँ विकसित करने का कार्य होगा। मध्यप्रदेश में नगरों की स्वच्छता के कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड प्राप्त कर रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल-संरक्षण के कार्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने प्रदेश में माफिया पर प्रभावी नियंत्रण के कदम उठाए हैं। अतिक्रमित भूमि मुक्त करवाई जा रही है, जो गरीबों के मकानों के लिए आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में हमारे शहर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं प्रशासन श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, आयुक्त नगरीय विकास एवं प्रशासन श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले भी वर्चुअली जुड़े।

किस कार्य के लिए कितनी राशि मिली- मिलियन प्लस नगरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 131 करोड़ 50 लाख और पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता के लिए 301 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। नॉन मिलियन नगरों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 199 करोड़ 60 लाख और स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल और संरक्षण के लिए 299 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

- प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। प्रयास करें कि हितग्राहियों को समय से किश्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- ग्रीष्म ऋतु में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि किसी जिले में पेयजल संकट न हो। इसके लिए आवश्यक तैयारियाँ की जाएँ।
- मानसून आगमन से पहले सड़कों में आवश्यक सुधार करें।
- प्रदेश के सभी शहरों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अर्बन क्षेत्र के जिन स्ट्रीट वेंडर्स (शहरी पथ विक्रेताओं) ने 10 हजार रूपए का ऋण चुकता कर दिया है, उन्हें अब 20 हजार रूपए का ऋण लेने के लिए प्रेरित करें।

22

48 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

रतलाम । कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रात: 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 17 अप्रैल को प्रात: 18 व दोपहर में 30 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रात: की षिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की षिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

16 अप्रैल गुरूवार को झोन क्रमांक 1 में विमलाबाई पति रघुवीर, बादल-दिलीप, राकेष-रतनलाल, अजय-विनोद, अनिल-अर्जून, विजय-फुलचन्द, झोन क्रमांक 2 में सुनील-ष्यामलाल, सोमदीप-सुदेष, ष्यामाबाई-कन्हैया, मीनाबाई-किषोर, विमलाबाई-पंकज, महेन्द्र-नेहरू, षिवकन्या-रमेष, प्रदीप-रामप्रसाद, पूर्णिमाबाई-चरण, राकेष-रामप्रसाद, संजय-बच्चु, मंजुबाई पति राजू, दोपहर की षिफ्ट में झोन क्रमांक 1 में विजय-षांतिलाल, सतीष-गोवर्धन, झोन क्रमांक 2 में नितिन-कमल, लताबाई पति संजय, विमलाबाई पति नारायण, बबीताबाई-ष्यामलाल, सुगनाबाई पति षंकर, दयाराम-मुंषी, मनुबाई पति किषोर, मनोरमाबाई पति मदन, संगीताबाई पति रमेष, दीपक-अन्नी, रेखाबाई पति ओमप्रकाष, ष्यामाबाई पति रामलाल, संध्याबाई पति सुरेष, अनिताबाई पति दीपक, आषाबाई पति मुकेष, मुन्नीबाई-मूलचन्द, षीलाबाई पति राधेष्याम, झोन क्रमांक 3 में रोहित-पवन, मनीश-विजय, सुनील-मनोहर, नजीर-कचरू, सुरेष-फतेहराम, झोन क्रमांक 4 में मुकेष-बाबुलाल, रामकन्या पति सोहन, मिनाक्षी-योगेष, सुनीताबाई पति षिवलाल इस तरह 48 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रषमन षुल्क में दी जा रही 20 प्रतिषत छूट

रतलाम । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेष षासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है। कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

जनसंपर्क रतलाम

19-4-22

स्वच्छता में उच्चतम रेटिंग के प्रयास करें नगरीय निकाय :

● वित्त आयोग की 931.50 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित ● बीते वर्ष से 35 प्रतिशत अधिक राजस्व पर, न

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम 19-4

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के प्रयास करें। नगरीय क्षेत्रों में अधो-संरचना विकास के कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना में और अच्छे परिणाम लाने के प्रयास करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की वित्त वर्ष 2021-22 की 931 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को सिंगल क्लिक से जारी करते हुए यह बात कही।

प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों को 432 करोड़ 50 लाख रूपए और नॉन मिलियन प्लस नगरों को 499 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई। इस अवसर पर रतलाम एनआईसी कक्ष में निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, डूडा प्रभारी श्री अरुण पाठक आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन को देखा व सुना गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व वसूली में अधिकांश शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष निकायों ने गत वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत

अधिक राजस्व प्राप्त किया है। इसके लिए निकाय बधाई के पात्र हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरीय विकास विभाग शहरों को बदलने के सद्प्रयासों में संलग्न है। नगरीय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रदेश में दो श्रेणियों के नगर हैं। प्रथम श्रेणी मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। मिलियन प्लस शहरों को अनुदान मिलने से वायु गुणवत्ता में सुधार, पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य बेहतर तरीके से होंगे। नॉन मिलियन शहरों को बेसिक अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग वे विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में उनके गत कार्यकाल में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की गईं। गत 2 वर्ष में भी नगरीय विकास क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अनेक योजनाओं में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। आज जारी की जा रही राशि से प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों के लिए और भी अच्छी सुविधाएँ विकसित करने का कार्य होगा। मध्यप्रदेश में नगरों की स्वच्छता के कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप

मध्यप्रदेश विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड प्राप्त क
वेंडर्स के कल्याण, प्रधानमंत्री आवास यो
संरक्षण के कार्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी
चौहान इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने
पर प्रभावी नियंत्रण के कदम उठाए हैं। अति
करवाई जा रही है, जो गरीबों के मकानों के
जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में ह
आगे बढ़ते रहेंगे। प्रमुख सचिव नगरीय विकास
मनीष सिंह, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री राघ
आयुक्त नगरीय विकास एवं प्रशासन श्री
श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम से प्रदेश के
वर्चुअली जुड़े।

किस कार्य के लिए कितनी राशि
प्लस नगरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए
लाख और पेयजल, सीवरेज और स्वच्छ
करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। नॉन मि
स्थानीय विकास कार्यों के लिए 199 करोड़
स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल और संरक्षण के
40 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

प्रसारण
19.4.22

ईद को लेकर तैयारी शुरू,पुरानी ईदगाह पर करवाई साफ-सफाई

रतलाम। रविवार को पुरानी ईदगाह का साफ सफाई व निरीक्षण किया गया । पिछले 2 वर्षों के बाद ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी ।जिसकी तैयारियों को लेकर समाज सेवियो के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष यास्मिन शेरानी , पूर्व पार्षद प्रतिनिधि शहजाद खान ,शाहिद हुसैन, नासिर भाई अख्तर भाई अनीस खान ने पुरानी ईदगाह का निरीक्षण किया व सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यास्मीन शेरानी ने बताया कि ईदगाह में 2 साल से नमाज नहीं होने की वजह से रखरखाव नहीं हो पाया था साथ ही यहां पर कई प्रकार की अव्यवस्था भी व्याप्त थी उसको जल्द ही निराकरण किया जाएगा इस अवसर पर नगर निगम सहा.स्वा.अधिकारी ए पी सिंह व कर्मचारी भी मौजूद रहे!

कर्मकार श्रमिक पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण कराएं

रतलाम। रतलाम जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया है कि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत पंजीकृत ऐसे समय से श्रमिक जिनके पंजीयन कार्ड की वैधता समाप्त हो चुकी है वे सभी श्रमिक विधिवत रूप से नवीनीकरण प्रक्रिया का पालन करें। अपने पंजीयन कार्ड के नवीनीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे मूल आवेदन, समग्र परिवार की जानकारी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो तथा विगत 1 वर्ष में 90 दिवस कर्मकार श्रमिक के रूप में नियोजित रहने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन स्थानीय लोक सेवा केंद्र ग्राम पंचायत या नगरी निकाय के माध्यम से जमा करें। अपीलीय प्रक्रिया- मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल अंतर्गत पंजीकृत ऐसे समस्त समीप जिनके पंजीयन को भौतिक सत्यापन के दौरान 20 वर्ष अपात्र चिन्हित किया जा चुका है वे श्रमिक अपनी पात्रता के दस्तावेज सहित अपनी अपील ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त अथवा नगर पालिका अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। श्रमिक के पंजीयन की पात्रता की जांच समग्र आईडी अथवा पोर्टल का उपयोग कर http://labour.mp.gov.in/corona/public/BenifitStatus.asp& के द्वारा की जा सकती है।

पत्रिका

19.4.22

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें

रतलाम । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में ष्वान पालते हैं वे अपने ष्वान का रजिस्टेªषन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस षाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत ष्वान पालकों द्वारा अपने ष्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा ष्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे ष्वानों एवं ष्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे ष्वान पालक जिन्होने अपने ष्वान का रजिस्टेषन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्टेªषन नहीं कराने वाले ष्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ष्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस षाखा में प्रति ष्वान पंजीयन षुल्क रूपये 1000/- एव लायसेंस षुल्क रूपये 500/- प्रति ष्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा ष्वान पालकों को अधिकतम् 2 ष्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा ष्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने ष्वान का रजिस्ट्रेषन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस षाखा में अनिवार्य रूप से करावे तथा अपने ष्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

17-4

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम । निर्माण एवं विध्वंस अपषिश्ट सामग्री के नियमानुसार निश्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिषन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपषिश्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

भुट्टा बाजार में लगी अवैध गुमटी को हटाएं

रतलाम ● शहर के व्यावसायिक व अन्य क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कर व्यावसायिक क्षेत्र व मुख्य मार्गों की सफाई के साथ ही नाले-नालियों की सफाई के निर्देश संबंधितों को देने के साथ ही भुट्टा बाजार में लगी अवैध गुमटी को हटाने के निर्देश भी दिए। श्री झारिया ने दो बत्ती, सैलाना बस स्टैण्ड, गीता मंदिर रोड, भुट्टा बाजार, डालू मोदी बाजार, नाहरपुरा, चांदनी चौक, नौलाईपुरा, धानमण्डी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर नाले नालियों की सफाई के निर्देश संबंधित को देते हुए नौलाईपुरा क्षेत्र के नाले की सफाई का कार्य तत्काल प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शहर के सभी सार्वजनिक शौचालय व यूरिनल की नियमित रूप से सफाई करवाई जाए । निरीक्षण के दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, अनवर कुरैशी, राजस्व उप निरीक्षक हरीश मिश्रा, झोन प्रभारी विनय चौहान, धर्मेन्द्र , कुलदीप भट्ट आदि उपस्थित थे।

19-4-22

मेले में आर्केस्ट्रा के कलाकारों ने नागरिकों का खुब मनोरंजन किया

17-4-22

रतलाम । नगर निगम द्वारा आयोजित तीन दिवसीय बरबड़ हनुमान मेले में बीती रात्री में निगम रंगमंच पर आयोजित आर्केस्ट्रा में कलाकारों ने फिल्मी गीतों व गीतों पर नृत्यों की प्रस्तुति देकर बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों का देर रात तक खुब मनोरंजन किया।

आर्केस्ट्रा की षुरूआत गायक प्रदीप पवांर ने गणेष वंदना व हनुमान जी के भजन के से की इसके पष्चात् कलाकारों ने अपने सुमधुर कंठ से बड़ी दूर से आये हैं प्या का तोहफा लाये है, सत्यम् षिवम् सुन्दरम्, याद आ रहा है तेरा प्यार, छुप गये सारे नजारे ओय बात हो गई, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे फिल्मी गीतो की प्रस्तुति दी वहीं राजस्थानी, फि व भजनों पर मनीशा ने आर्कशक नृत्यों की प्रस देकर नागरिकों का देर रात तक भरपुर मनो किया। प्रारंभ में पूर्व पार्शद श्री प्रहलाद पटेल आर्केस्ट्रा के कलाकार मोहम्मद अय्यूब, प्रदीप प माधुरी, मनीशा, जितेन्द्र चौहान, रमन हारोड़, सहगल, राजेष बैरागी, आनन्द नागरकर आदि स्वागत पुश्प गुच्छ व पुश्पहारों से किया।

19.4.22

गर्म हवा के थपेड़े कर रहे बेचैन

तापमान में बढ़ोतरी से दोपहर में शहर की सड़कों पर पसर रहा सन्नाटा

रतलाम। जिले में मौसम में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। दिन और रात के तापमान में मामूली घट-बढ़ चल रही है। सोमवार को दिन के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई, वहीं रात के तापमान में मामूली गिरावट आई। गर्म हवा के थपेड़े सभी को बेचैन कर रहे हैं, वहीं दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों द्वारा तरह-तरह के जतन किए जा रहे हैं। बगीचों के साथ स्वीमिंग पूल में भी भीड़ बढ़ने लगी है।

जिलेवासियों को सूरज के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। अप्रैल माह में आसमान से आग बरस रही है। तापमान में बढ़ोतरी से आमजन के पसीने छूट रहे हैं। घर-दुकान, प्रतिष्ठानों में पंखे-कूलर भी राहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं। रविवार के मुकाबले सोमवार को अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, वहीं न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। सुबह की आर्द्रता 41 प्रतिशत व शाम की 18 प्रतिशत रही, जो रविवार को क्रमशः 43 व 16 प्रतिशत थी।

कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल में जलक्रीड़ा करते हुए बच्चे। ●नईदुनिया

जरूरी काम होने पर निकल रहे बाहर

सैलाना। गर्मी से चारों ओर लोग परेशान हो रहे है। गर्मी से बचने के लिए लोग शीतलपेय पदार्थ का उपयोग कर रहे है।

जरूरी काम होने पर ही लोग दोपहर में घरों से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर होते-होते बाजार में सन्नाटा पसरने लगा है। मुख्य मार्ग पर इक्का-दुक्का लोग ही देखे जा रहे है।

सुबह-शाम शीतलपेय पदार्थ की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लग रही है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए तरह-तरह के जतन भी कर रहे हैं। दो पहिया वाहन चालक गर्मी से बचाव के लिए मुंह पर गमछा लपेट कर वाहन चला रहे है।

पत्रिका

19-4-22

न्यूज गैलरी

11 लोगों से वसूला जुर्माना

रतलाम। नगर निगम द्वारा शहर में गंदगी फैलाने और अमानक पालिथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ सतत कार्रवाई की जा रही है। निगम आयुक्त के निर्देशानुसार मनोज जोशी व राज रतन से 200-200 रुपये, कालू भाई, पवन चौरसिया, अंकित चौरसिया, शाहनवाज खान, चांद मोहम्मद, इकरार खान, जीवन, गंगाबाई व संतोष कुमार से 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पाट फाइन दल ने सभी को भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने व अमानक पालिथीन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी। कार्रवाई कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट आदि द्वारा की गई।

रात्रिकालीन सफाई के दो कर्मचारियों का वेतन काटा

रतलाम। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा रविवार को निरीक्षण किया गया। इस दौरान महेश-प्रभुदयाल व रघु-कन्हैया कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाए गए। संबंधित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के निर्देश संबंधित को दिए गए।

सुधार की शुरुआत • ट्रैफिक सिग्नल के बाद यातायात सुधारने के लिए दूसरा बड़ा फैसला

24 अप्रैल से सड़कों के किनारे बैठकर फल-सब्जी नहीं बेच सकेंगे, स्थान तय

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सुगम हो शहर का ट्रैफिक

शहर के अव्यवस्थित यातायात को सुधारने और बार-बार जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सोमवार को दूसरा बड़ा फैसला हुआ है। 24 अप्रैल से फल-सब्जी विक्रेता यहां वहां सामान नहीं बेच सकेंगे। स्थान तय किए हैं, जहां लोग पहुंचकर खरीदारी करेंगे। ये फैसला 20 नवंबर की मीटिंग में हो गया था, अमल अब होगा।

सोमवार को भी तोपखाना में जाम लग जाने के कारण लोगों को खूब परेशान होना पड़ा। इधर, सोमवार को कलेक्टर ने निगमायुक्त को कहा है कि 24 अप्रैल से सभी सब्जी, फल विक्रेता शहर में विक्रय नहीं करेंगे। उनको त्रिवेणी, सैलाना ब्रिज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने और जवाहर नगर श्मशान के समीप विक्रय के लिए स्थान दिया जा रहा है। स्थान तय हो जाने से लोग तय स्थान पर ही खरीदारी करने पहुंचेंगे। हालांकि, अब इस पर नगर निगम को काम करना होगा। वहां व्यवस्थाएं जरूरी हैं। शहर को नो-हॉकर्स जोन बनाने का फैसला 20 नवंबर को हुई यातायात की मीटिंग में हुआ था।

इन मार्गों को होना था वन-वे, यह प्लान अब भी कागजों में

तोपखाना से हरदेव लाला की पीपली तक सोमवार को दोपहर 12 बजे ट्रैफिक जाम रहा। यहां लोगों को करीब 20 मिनट तक परेशान होना पड़ा।

- नवंबर में हुई मीटिंग में शहर में वन-वे की शुरुआत करने की चर्चा हुई थी।
- डालूमोदी बाजार, गणेश देवरी, चौमुखीपुल, रानीजी का मंदिर, तोपखाना, घास बाजार, लोकेंद्र टॉकीज, सैलाना बस स्टैंड को वन-वे करना था।
- 24 नवंबर तक प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन अब तक नहीं हो सका है।
- शहर में पार्किंग लाइन डाली थी, शुरुआत में कार्रवाई हुई, लेकिन अब बाजार क्षेत्र में पार्किंग लाइन के बाहर खड़े वाहन दिखते हैं।

ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे

इधर, हाल ही में शहर के तीन चौराहों पर सिग्नल लगाने का फैसला हुआ है। इसमें लोकेंद्र टॉकीज, सैलाना बस स्टैंड और दो बत्ती चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था शुरू होगी। 93 लाख रुपए में यह टेंडर लगाए जाएंगे।

निगम टीम चिह्नित करेगी अतिक्रमण

अवैध कॉलोनियों और सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद शहर के बड़े अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। आयुक्त सोमनाथ झारिया की टीम अतिक्रमणों को चिह्नित कर हटाने की कार्रवाई होगी। यह फैसला सोमवार को टीएल मीटिंग में लिया। साथ ही वर्धमान नगर विकसित करने वाले कॉलोनाइजर द्वारा गड़बड़ी किए जाने पर एफआईआर कराने का भी निर्णय लिया गया।

भास्कर 19.4.22

फिर 34 सफाई कर्मचारी मिले गैरहाजिर, एक दिन का वेतन काटा

19-4

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सफाई व्यवस्था से कर्मचारियों का बिना सूचना और अनुमति के गैरहाजिर रहने का सिलसिला नहीं थम रहा। सोमवार सुबह व दोपहर की शिफ्ट 34 सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिले।

खुलासा पर्यवेक्षकों की चेकिंग में हुआ। इसमें सुबह की शिफ्ट के 27 और दोपहर की शिफ्ट के 7 कर्मचारी शामिल है। आयुक्त सोमनाथ झारिया सभी का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। इनमें जोन एक के 8, जोन दो के 18, जोन तीन के 4, जोन चार के 3 कर्मचारी शामिल है।

गंदगी व अमानक पॉलीथिन उपयोग पर 11 पर जुर्माना

रतलाम | स्वच्छ सर्वेक्षण के सर्वे चलने के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने और अमानक पॉलीथिन का उपयोग करने पर सोमवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया। कार्रवाई स्पॉट फाइन की टीम ने की। मनोज जोशी व राज रतन पर 200 रुपए, कालु भाई, पवन चौरसिया, अंकित चौरसिया, शाहनवाज खान, चांद मोहम्मद, इकरार खान, जीवन, गंगाबाई, संतोष कुमार पर 100 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया।

19.4 भास्कर

शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रखें

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने राजस्व अधिकारियों की बैठक सोमवार प्रातः आयोजित की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखें। यदि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट आती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर तत्काल दर्ज कराई जाए। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के विरुद्ध तत्काल एक्शन ली जाए। कलेक्टर ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, एसडीएम राजेश शुक्ला, तहसीलदार अनीता चौकोटिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि समर्थन मूल्य पर जिले में गेहूं उपार्जन कार्य में कोई बाधा नहीं आए। किसी भी समस्या पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली खंड स्तरीय समिति तत्काल एक्शन ले। इस संबंध में एसडीएम ध्यान रखें, कोई भी शिकायत आने पर मौके पर जाकर समस्या का निराकरण करें।

कलेक्टर ने बैठक में राजस्व अधिकारियों के मूलभूत कार्यों की समीक्षा की। प्राकृतिक आपदाओं में आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली सहायता की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि तहसील कार्यालय में आदेश पारित होने के पश्चात बाबुओं की ढिलाई के कारण से संबंधित व्यक्ति को भुगतान अटका नहीं रहे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की गई। इसमें पिपलोदा तहसीलदार का परफॉर्मेंस खराब पाया गया। आलोट में भी कार्य में कमी पाई गई। रावटी में सबसे खराब कार्य पाया गया जबकि जावरा तहसीलदार का कार्य मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बहुत अच्छा पाया गया। कलेक्टर द्वारा स्वामित्व योजना, धारणाधिकार, वन अधिकार पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि उपलब्ध कराने के कार्य की समीक्षा भी की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिन आयकरदाताओं द्वारा प्राप्त कर ली गई है उनसे वसूली की जाना है उनकी संख्या 6802 है।

19-4

नवभारत 19.4.22

मुख्यमंत्री आज नगरीय निकायों को अंतरित करेंगे 931 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि

भोपाल ● 18 अप्रैल (वा)

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित 931 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी करेंगे। इसमें चार मिलियन प्लस शहरों (दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले) को 432 करोड़ 50 लाख एवं नॉन मिलियन प्लस शहरों को 499 करोड़ रुपए की राशि अंतरित होगी। इस राशि से इन शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार, पेयजल योजनाओं, सीवरेज एवं स्वच्छता के कार्य तथा आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास के कार्य किए जा सकेंगे।

सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ की है कार्रवाई - नरोत्तम

भोपाल ● मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज स्पष्ट कहा कि सरकार ने दंगाइयों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की है और जो भी न्यायालय जाना चाहता है, वो जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि खरगोन में अब पूर्णतया सामान्य स्थिति है और प्रशासन मॉनिटरिंग कर आवश्यकतानुसार ढील दे रहा है। मिश्रा ने मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ कुछ संगठनों के उच्चतम न्यायालय जाने से जुड़े सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने कार्रवाई के पहले किसी कौम को ध्यान में नहीं रखा, दंगाइयों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिसे न्यायालय जाना है, वो जाए, न्यायालय का जो आदेश देगा, वह सर-माथे है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि राज्य में हनुमान जयंती पर 279 स्थानों पर शांतिपूर्वक शोभायात्रा एवं जुलूस निकला है। साथ ही उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक कार्यक्रम के लिए वे पुलिस प्रशासन को बधाई देते हैं।

स्वदेश 19-4-22

स्वदेश 19.4.22

पानी के लिए तरस रहा बाजना बसस्टैंड

यात्री के साथ दुकानदार भी परेशान

रतलाम : संजय एम.कोठारी

रतलाम के बसस्टेंड पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। हां न तो पानी का इंतजाम है और नहीं बस के इंतजार के लिए यात्री प्रतीक्षालय) बैठने की व्यवस्था। इससे यात्रियों को रेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

हम बात कर रहे हैं खासतौर पर जिला मुख्यालय के बाजनाबसस्टेंड की जो काफी समय से अव्यवस्थाओं से जूझ हा है। रावटी, शिवगढ़, बाजना, कुशलगढ़, कुदनपुर तक की सें इस बसस्टेंड से गुजरती है बावजूद इसके यहां स्थानीय शासन की लापरवाही की वजह से मूलभूत सुविधाओं का भाव है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बसस्टेंड पर यात्रियों को पीने का पानी तक नहीं मिलता है। एक सौ दस किलोमीटर की दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को भी यहां पानी नहीं मिलने से कई बार तो प्यासे ही निकल पड़ते है।

बाजना बसस्टेंड पर पानी का उचित साधन नहीं होने से बसस्टेंड की दुकान वाले भी पानी के लिए परेशान हैं। इस वजह से यहां की दुकानों पर ग्राहक को बोतल भर पानी नहीं मिलता है। आधा अप्रैल बीत चुका है और अभी मई-जून तो बाकी हैं लेकिन बसस्टेंड पर पीने के पानी का आज भी कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की तो मंशा हैं कि पानी के लिए किसी को परेशानी नहीं होने देंगे लेकिन बाजनाबसस्टेंड पर ना केवल दुकानदार बल्कि यात्रीगण भी पीने के पानी के लिए काफी परेशान है। दुकानदारों ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का ध्यान बाजना बसस्टेंड की ओर खींचते हुए यहां पानी का इंतजाम करने की गुहार लगाई है ताकि दुकानदारों के साथ यात्रियों को भी पीने का पानी आसानी से मिल सके। ऐसा भी नहीं कि इस बसस्टेंड पर यात्रियों की संख्या कम रहती हो। त्यौहार और शादी की सीजन के समय पर तो ठीक वैसे भी इस बसस्टेंड पर

गूगल मैप पर उपलब्ध हैं। दिव्यांग शौ

नगर पालिक निगम, रतलाम | नगर पालिक निगम

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022

कब आएगा.. बाजना बसस्टैंड पर फ्रिजर का स्टैंड आज भी फ्रिजर के लौटने की बाट जो रहा है।

निगम वाले फ्रिजर ले गए

रतलाम, नप्र। तत्कालीन कलेक्टर रुचिका चौहान के समय बाजना बसस्टेंड पर ना केवल पानी का इंतजाम करवाया था बल्कि वहां एक छोटा फ्रिजर भी लगाया था। इस फ्रिजर से यात्रियों के अलावा बसस्टेंड के दुकानदार को भी ठंडे पानी की सुविधा मुहैया हुई थी। बस चालकों और क्लीनरों को भी ठंडा पानी मिलता था। यहां शुरुआत में तो फ्रीजर के ऐसे ही रख दिया गया था लेकिन बाद में बकायदा उसके लिए पक्का स्टेंड भी बनवाया था जिससे यात्रियों के लिए दुकानदारों को पीने के पानी की बेहत्तर सुविधा मिल रही थी लेकिन बड़ा फ्रिजर लगाने के नाम पर निगम वाले यहां का फ्रिजर निकालकर ले गए तब से बसस्टेंड पानी के लिए तरस रहा है। आज तक ना तो यहां कोई बड़ा फ्रिजर आया और नहीं यहां से ले जाया गया छोटा फ्रिजर फिर से यहां आ पाया।

आज भी बसस्टेंड पर फ्रिजर के लिए बना स्टेंड सूना होकर फ्रिजर का इंतजार कर रहा है। दुकानदारों ने फ्रिजर के साथ पानी का इंतजाम करने की मांग की है।

धूप और गर्मी से जूझ रहे यात्री

आदिवासी अंचल के यात्रियों की आवाजाही बहुतायत में रहती है। आदिवासी अंचल के ठेट बाजना और उसके आगे तक के मजदूर मजदूरी के लिए बस का सफर कर यहां पहुंचते और यहीं से वापस गंतव्य की ओर जाते है। लेकिन यहां यात्रियों के लिए ना तो छांव की कोई व्यवस्था हैं और नहीं पानी का कोई इंतजाम है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नगर निगम यहां पानी के लिए एक नल तक नहीं लगवा पाया है ताकि होटल वाले वहां से पानी भर पाए। हैडपंप तक भी सुविधा नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें ठेट दीनदयालनगर और कलीमी कॉलोनी की पानी की टंकी से पानी लेकर आना पड़ता है।

यात्रियों को तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच खुले में बैठकर बसों का इंतजाम करना पड़ता है। अकेले बाजना बसस्टेंड की बात करें तो दिनभर में यहां से कई बसें यात्रियों को ढोती रहती है, हजारों यात्री बसों से सफर करते है लेकिन यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यात्री धूप, गर्मी का शिकार होने के लिए मजबूर होते रहते है एक बार फिर भी धूप और गर्मी को सहन कर लेते है लेकिन कंठ की प्यास को सहन नहीं कर पाते है और वे पानी के लिए बसस्टेंड पर इधर-उधर भटकते रहते हैं।

यही हाल दूसरे अन्य बस स्टेंड का भी है। रतलाम शहर के लिए बातें तो बड़ी-बड़ी की जाती है (लेकिन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी बसस्टेंड को छोड़ दिया जाए तो) बाजना बसस्टेंड के अलावा दूसरे बसस्टेंडो को भी देखे वहां के भी ऐसे ही हाल है जहां यात्रियों के लिए छांव-पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

बाजना बसस्टेंड, उज्जैन-बड़नगर और खाचरौद की बसों के स्टेंड के अलावा सैलाना बसस्टेंड पर भी यात्री प्रतीक्षालय की सुविधा नहीं होने से यात्रियों को बैठने की जगह तक नहीं मिलती है। ऐसे में या तो यात्री खड़े रहते है या फिर दुकानों के आसपास जहां जगह मिलती है या फिर जमीन पर ही बैठे रहते है।

प्रभात किरण
18-4-22

प्रधानमंत्री आवास की किस्त में देर हुई तो समझूंगा दाल में कुछ काला है : सीएम

मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को ट्रांसफर किए 931 करोड़ रुपए

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल
मो.नं. 9425078939

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को नगरीय निकायों के लिए 931 करोड़ रुपए की राशि एक क्लिक के जरिये ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के हितग्राही को किस्त मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें देर हुई तो मैं समझूंगा कि दाल में कुछ काला है। भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में कहा कि राजस्व वसूली में अधिकतर

शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष निकायों ने पिछले साल की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक राजस्व जुटाया है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। नगरीय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं।

अतिक्रमण वाली भूमि पर बनेंगे गरीबों के घर

नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास से प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.15 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। माफिया के विरुद्ध बुलडोजर चलाने का काम चल रहा है। अतिक्रमण मुक्त भूमि गरीबों के आवास बनाने के लिए आरक्षित की जाएगी। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिलाने जैसे क्षेत्रों में भी मप्र के कामकाज का जिक्र किया।

पीपुल्स 19-4

पीपुल्स 19-4-22

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

आपत्तिजनक पोस्ट, सांप्रदायिक सदभाव बिगाड़ने व शासकीय भूमि से अतिक्रमण वालों के खिलाफ तुरंत करे कार्यवाही

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने राजस्व अधिकारियों की बैठक सोमवार प्रातः आयोजित की कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखें यदि कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट आती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस थाने में एफ आई आर तत्काल दर्ज कराई जाए। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के विरुद्ध तत्काल एक्शन ली जाए, कलेक्टर ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत एसडीएम राजेश शुक्ल तहसीलदार श्रीमती अनीता चौकोटिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि समर्थन मूल्य पर जिले में गेहूं उपार्जन कार्य में कोई बाधा नहीं आए किसी भी समस्या पर एसडीएम की अध्यक्षता वाली खंड स्तरीय समिति तत्काल एक्शन ले इस संबंध में एसडीएम ध्यान रखें कोई भी शिकायत आने पर मौके पर. जाकर समस्या का निराकरण करें। कलेक्टर ने बैठक में राजस्व अधिकारियों के मूलभूत कार्यों की समीक्षा की प्राकृतिक आपदाओं में आरबीसी 6-4 के तहत दी जाने वाली सहायता की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि तहसील कार्यालय में आदेश पारित होने के पश्चात बाबुओं की ढिलाई के कारण से संबंधित व्यक्ति को भुगतान अटका नहीं रहे।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की गई इसमें पिपलोदा तहसीलदार का परफॉर्मेंस खराब पाया गया। आलोट में भी कार्य में कमी पाई गई। रावटी में सबसे खराब कार्य पाया गया जबकि जावरा तहसीलदार का कार्य मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बहुत अच्छा पाया गया। कलेक्टर द्वारा स्वामित्व योजना धारणाधिकार वन अधिकार पट्टा धारकों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सम्मान निधि उपलब्ध कराने के कार्य की समीक्षा भी की गई। बैठक में बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिन आयकर दाताओं द्वारा प्राप्त कर ली गई है उनसे वसूली की जाना है उनकी संख्या 6802 है।

इन्दौर समाचार

इन्दौर समाचार
19-4-22

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

अमृत योजना● केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की गाइडलाइन, कुल 50 लाख रुपये की लागत आएगी, नगर निगम ने जारी किए टेंडर

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर को गंदे पानी से मुक्त करने के लिए अमृत योजनांतर्गत सीवरेज प्रोजेक्ट में बनाए गए दोनों सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर अब 25-25 लाख रुपये की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि सीसीटीवी से आनलाइन डाटा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जाएगा। इससे प्लांट पर पानी साफ करने सहित अन्य गतिविधियों पर भी आनलाइन निगरानी की जा सकेगी।

मालूम हो सीवरेज प्रोजेक्ट में शहर में 276 किमी लंबी लाइन डाली गई है। इसके साथ ही खेतलपुर व करमदी में एसटीपी प्लांट से कुल 37.5 एमएलडी पानी रोज साफ किया जा सकता है। दोनों प्लांट से अभी पानी साफ किया जा रहा है। नगर निगम यह पानी निर्माण, उद्यान व अन्य गैर पेयजल कार्यों के लिए रियायती दर पर दे रहा है। खेतलपुर एसटीपी की क्षमता 21.5 एमएलडी व करमदी एसटीपी की 16 एमएलडी है। ट्रीटमेंट के लिए प्लांट में एमसीसी बिल्डिंग, पंपिंग स्टेशन, सेप्टी हाउस सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। निगम कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगने से स्थानीय स्तर पर भी निगरानी होगी। दोनों एसटीपी काफी बड़े हैं। सुरक्षा के लिए भी सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है।

जीएफसी सर्वे के लिए पहुंची टीम, अमला अलर्ट

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में गार्बेज फ्री सिटी सर्वे के लिए टीम रतलाम पहुंच गई है। इसे लेकर निगम अमला भी अलर्ट है। स्वच्छता की रैंकिंग में जीएफसी से मिलने वाले नंबर अहम हैं। निगम ने फाइव स्टार रैंक के लिए दावा किया है। इसके लिए कचरा संग्रहण वाहनों को पूरी क्षमता के साथ लगाया गया है।

इस बार सर्वेक्षण 7500 अंक का है जबकि पिछले सर्वेक्षण में 6000 अंक थे। इसमें 2250 अंक सर्टिफिकेशन के निर्धारित किए हैं। पिछले साल 1800 अंक निर्धारित थे। शहर पूरी तरह खुले में शौच मुक्त है या नहीं। इसमें सेवन स्टार सिटी के 1250 अंक, फाइव स्टार सिटी के 1000 अंक, थ्री स्टार सिटी के 800 अंक, वन स्टार सिटी के 500 अंक, ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट के 400, ओडीएफ प्लस प्लस सर्टिफिकेट के 800 अंक, और वाटर प्लस सर्टिफिकेट के 1000 अंक निर्धारित किए हैं।

111 मीट्रिक टन कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सोमवार को 111 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 29185 किलो, ट्रैक्टर-ट्राली से 13055 किलो, मैजिक सूखा कचरा 45785 किलो, मैजिक गीला कचरा 23860 किलो, सेनेटरी कचरा तीन किलो, घरेलू हानिकारक कचरा 3.1 किलो इस तरह कुल 111891.1 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

करमदी स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ●नईदुनिया

नई दुनिया
19.4.22

टीएल बैठक **कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों को दिए निर्देश**

हटाए जाएंगे बड़े अतिक्रमण, 24 से सड़कों पर नहीं बिकेंगे फल-सब्जी

19-4-22

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर में बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, उनको हटाने की कार्रवाई होगी। जिन कालोनाइजर, भूमाफियाओं द्वारा जमीन के मामलों में गड़बड़ी की है उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे।

यह निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए। इस दौरान कलेक्टर ने वर्धमान नगर कालोनाइजर द्वारा की गई गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए।

टीएल बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम। • नईदुनिया

सीएम हेल्पलाइन में गड़बड़ी, कृषि विभाग अमले का वेतन रुकेगा : कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा शिकायतों के निपटान में धीमी गति पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कृषि विभाग वर्तमान में 30 वीं व लीड बैंक 48वीं रैंक पर है। कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग सैलाना विकासखंड में एसडीएम सैलाना द्वारा की गई जांच के दौरान 23 कम्युनिटी हेल्थ आर्गेनाइजर अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने सभी की अनुपस्थिति दिवस की सैलरी काटने के निर्देश दिए।

तय स्थानों पर बैठेंगे सब्जी विक्रेता

कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि 24 अप्रैल से सभी सब्जी, फल विक्रेता शहर में विक्रय नहीं करेंगे, उनको त्रिवेणी, सैलाना ब्रिज के नी[illegible] साक्षी पेट्रोल पंप के सामने तथा जव[illegible] नगर शमशान के समीप विक्रय [illegible] लिए स्थान दिया जा रहा है। कले[illegible] ने आत्मा परियोजना के संचा[illegible] नरगेश को निर्देशित किया कि वह [illegible] सप्ताह के दौरान उनके द्वारा संपा[illegible] कार्यों की जानकारी कलेक्टर के स[illegible] प्रस्तुत करें। आयुष्मान कार्ड निर्माण [illegible] समीक्षा में सैलाना, बाजना में कार्य [illegible] गति अत्यंत धीमी पाई गई। कलेक्ट[illegible] नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि [illegible] धीमी गति से कैसे काम चलेगा, कार्य[illegible] रफ्तार बढ़ाई जाए।

प्रधानमंत्री के संदेश से अवगत कराया गया

नई दुनिया
19-4-22

रतलाम। संपूर्ण भारत में भाजपा द्वारा सामाजिक न्याय पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व कार्यक्रम के जिला प्रभारी इब्राहिम शेरानी, कार्यक्रम संयोजक व जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंसूर जमादार, सहसंयोजक व जिला मीडिया प्रभारी मुबारिक शेरानी द्वारा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में असंगठित श्रमिकों के सम्मेलन का आयोजन कर वेंडिंग नेम प्लेट, प्रधानमंत्री के संदेश को अतिथियों द्वारा वितरित कराया गया। कार्यक्रम मे भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अशोक पोरवाल, जिला महामंत्री निर्मल कटारिया, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष इब्राहिम शेरानी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजिका अनिता कटारिया, जिला मंत्री सोना शर्मा, जिला भंडार प्रभारी दशरथ पाटीदार, मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, मंडल महामंत्री राकेश परमार, धर्मेंद्रसिंह, महिला मोर्चा जिला महामंत्री महिला मोर्चा अनिता पाहुजा मंचासीन रहे। अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बब्लू पटेल, वाजिद खान, रईस कुरैशी, सलीम नेताजी, हमीद खान, लतीफ भा, शेख अजरुद्दीन, जाकिर हुसैन फक्का, अजहर मंसूरी, शरीफ कुरैशी, इमरान खान, अकबर कुरैशी आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आभार जिला मीडिया प्रभारी मुबारिक शेरानी ने माना। जानकारी में जिला कार्यालय मंत्री इसरार रहमानी ने दी।

निगमायुक्त बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, हटाने क

◆ भूमि की गड़बड़ी वाले मामलों में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश ◆ कलेक्टर ने समय

19-4-22

प्रसारण न्यूज़ ◆ रतलाम

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर में बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिन कॉलोनाइजर्स, भू माफियाओं द्वारा जमीन के मामलों में गड़बड़ी की गई है, उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे। इस दौरान कलेक्टर ने वर्धमान नगर कॉलोनाइजर द्वारा की गई गड़बड़ी पर उसके विरुद्ध एफ आई आर पुलिस थाने में दर्ज कराने के निर्देश एस डी एम को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, एस डी एम राजेश शुक्ला, जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी, डूडा परियोजना अधिकारी अरुण पाठक, जिला महिला बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा, सी एम एच ओ डॉ. प्रभाकर ननावरे आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा शिकायतों के निपटान में धीमी गति पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कृषि विभाग वर्तमान में 30 वीं रैंक पर है तथा लीड बैंक 48 वीं रैंक पर है। कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के तहत सैलाना विकासखंड में एसडीएम सैलाना द्वारा की गई जांच के दौरान 23 कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर अपने कर्त्तव्य

तथा
स्थान

प्रसारण

19-4-22

नगरीय निकायों के लिए सरकार ने खोला खजाना

...में होगा प्रदेश के निकायों का विकास

दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले को 432 करोड़ 50 लाख एवं नॉन मिलियन प्लस शहरों को 499 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

विनोद शर्मा, स्वतंत्र समय, भोपाल

मप्र के विकास के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए सरकार का खजाना खोला है। सोमवार को शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित 931 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की। इसमें चार मिलियन प्लस शहरों (दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले) को 432 करोड़ 50 लाख एवं नॉन मिलियन प्लस शहरों को 499 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है।

इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि मिलियन प्लस शहरों में पेयजल, स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए भी आज 301 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के मित्रों से मेरा आग्रह है कि इस राशि का बेहतर उपयोग करते हुए निश्चित समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करें।हमारे जिन शहरों की आबादी दस लाख से कम है, उनको भी दो अनुदान जारी किये गये हैं। पहले 500 करोड़ और अब 499 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि का उपयोग निकाय विभिन्न विकास कार्यों एवं पेयजल तथा सॉलिड मैनेजमेंट आदि के लिए कर सकता है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि इस राशि से इन शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार, पेयजल योजनाओं, सीवरेज एवं स्वच्छता के कार्य तथा आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास के कार्य किये जा सकेंगे। मिलियन प्लस शहर वायु गुणवत्ता सुधार संबंधी कार्य के लिये 131 करोड़ 50 लाख रूपये और पेयजल, सीवरेज एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों में 301 करोड़ रूपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नॉन मिलियन शहर 199 करोड़ 60 लाख रूपये स्थानीय विकास के कार्य और 299 करोड़ 40 लाख रूपये स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल, जल संरक्षण संबंधित आदि कार्य में व्यय करेंगे।

अतिक्रमण से मुक्त भूमि पर बनेंगे गरीबों के आवास

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छता, प्रधानमंत्री आवास, पथ विक्रेता को ऋण दिलाने सहित अन्य क्षेत्रों में लगातार पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री के प्रयास से प्रधानमंत्री आवास योजना में एक लाख 15 हजार आवास स्वीकृत हुए हैं। माफिया के विरुद्ध बुलडोजर चलाने का काम चल रहा है। अतिक्रमण मुक्त भूमि गरीबों के आवास बनाने के लिए आरक्षित की जाएगी।

■ ■ ■

दाल में कुछ काला है

...कुछ काला है और हम भ्रष्टाचार को ...र बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने ... शहरी विकास के काम तेजी से चल ..., इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर को ...ता में सुधार, सिटी एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। पेयजल और स्वच्छता के लिए भी प्रावधान किया है। 10 लाख से कम आबादी शहरों को 499 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इस राशि का उपयोग वेतन-भत्ते को छोड़कर विकास कार्यों में किया जाना है। योजना बनाकर समयसीमा में लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करें। पेयजल की आपूर्ति के काम को प्राथमिकता में करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हमें देश में नंबर एक पर रहना है। मानसून के पहले शहरी क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव का काम पूरा कर लें। प्रधानमंत्री आवास के लिए पर्याप्त राशि है। समय से किस्त हितग्राही के खाते में जमा करें।

स्वतन्त्र समय 17/5/22

अतिक्रमण चिन्हित करें, हटाने की कार्रवाई की जाए

ामलों में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश ◆ कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की बैठक में समीक्षा की

अपर कलेक्टर
ात, निगमायुक्त
एस डी एम राजेश
आपूर्ति अधिकारी
डूडा परियोजना
ठक, जिला महिला
धिकारी रजनीश
व ओ डॉ. प्रभाकर
थत थे।
ुख्यमंत्री हेल्पलाइन
रणों की समीक्षा के
तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक
निपटान में धीमी गति पर सख्त
। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कृषि विभाग वर्तमान में 30 वीं रैंक पर है तथा लीड बैंक 48 वीं रैंक पर है। कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के तहत सैलाना विकासखंड में एसडीएम सैलाना द्वारा की गई जांच के दौरान 23 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपने कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने सभी ऑफिसर्स की अनुपस्थिति दिवस की सैलरी काटने के निर्देश दिए।

रतलाम शहर में व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि 24 अप्रैल से सभी सब्जी, फल विक्रेता शहर में विक्रय नहीं करेंगे, उनको त्रिवेणी, सैलाना ब्रिज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने तथा जवाहर नगर शमशान के समीप विक्रय के लिए स्थान दिया जा रहा है।

कलेक्टर ने कृषि विभाग के तहत आत्मा परियोजना के संचालक नरगेश को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह के दौरान उनके द्वारा संपादित कार्यों की जानकारी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा भी की गई। सैलाना, बाजना में कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई।

बाजना में 30 हजार कार्ड बनना शेष है। सैलाना में 11 हजार कार्ड बनाए जाना है। कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी धीमी गति से कैसे काम चलेगा, कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाए। समर्थन मूल्य पर जिले में गेहूं की भी समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिन स्थानों से शिकायत प्राप्त होगी, उन स्थानों पर केंद्र प्रबंधक नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

7/2005

7-4-22

गरीबों को आवास • पूरा अंशदान एकमुश्त भरने वाले हितग्राहियों को प्राथमिकता भी मिलेगी

पीएम आवास योजना : 420 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए 741 परिवारों ने जमा कराए 6.40 करोड़ रुपए

भास्कर संवाददाता | रतलाम 19-4

डोसीगांव और बंजली में बने 420 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स लेने की चाहत में सोमवार तक 741 परिवारों ने 6.40 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। 121 हितग्राहियों ने 3.50 लाख रुपए का पूरा अंशदान तथा 620 ने अंशदान का 10 प्रतिशत यानी 35000 रुपए जमा करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाया है।

नगर निगम के पास नॉन स्लम एरिया के 2240 हितग्राहियों की सूची है। इन्हें फ्लैट्स देने के लिए निगम ने 5 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन चालू किए थे। पूरा अंशदान एक मुश्त भरने वाले हितग्राहियों को प्राथमिकता भी मिलेगी। विधायक चेतन्य काश्यप ने बताया रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए हैं। अब जल्द ही बाकी की प्रक्रिया निपटाकर हितग्राहियों को फ्लैट्स आवंटित किए जाएंगे।

डोसीगांव में तैयार फ्लैट्स, जो हितग्राहियों को अलॉट किए जाना हैं।

आवंटन के बाद बचे हुए की बनेगी वेटिंग लिस्ट

अफोर्डेबल हाउस (एएचपी) घटक में बने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स से ज्यादा रजिस्ट्रेशन राशि जमा होने पर पहले तो वरियता के आधार पर 420 फ्लैट्स आवंटित कर दिए जाएंगे। उसके बाद बचे हुए पंजीयनकर्ताओं की वेटिंग लिस्ट में बनेगी। इन्हें नए फ्लैट्स बनने पर सूची में प्राथमिकता के अनुसार मकान अलॉट किए जाएंगे।

शहर में पीएम आवास योजना अब तक

योजना	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी	एमआईजी
डोसीगांव प्रथम चरण	396	96	0
डोसीगांव द्वितीय चरण	196	144	0
मुखर्जी नगर	36	0	96
बंजली	224	192	0
अब तक बन चुके	852	432	96

भास्कर 19-4-22

24 अप्रैल से नई व्यवस्था के तहत बैठेंगे सब्जी विक्रेता

फिर होगा बदलाव: शहर में नहीं बैठ सकेंगे सब्जी वाले, प्रशासन ने चिन्हित किए स्थान

पत्रिका पब्लिक इश्यू

वर्धमान नगर कॉलोनाइजर की गड़बड़ी पर एफआईआर कराने के दिए निर्देश

पत्रिका 19-4

रतलाम. शहर में यातायात सहित अन्य व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए अब सब्जी व्यवसायी शहर की सड़कों पर बैठ सब्जी नहीं बेच सकेंगे। इनके लिए प्रशासन ने एक बार फिर से स्थान तय किए हैं, वहीं पर बैठकर ये लोग सब्जी विक्रय कर सकेंगे। प्रशासन ने 24 अप्रैल से नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश नगर निगम को दिए हैं।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निगमायुक्त सोमनाथ झारिया को सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निर्देशित किया कि 24 अप्रैल से सभी सब्जी, फल विक्रेता शहर में विक्रय नहीं करेंगे। उनको त्रिवेणी, सैलाना ब्रिज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने तथा जवाहर नगर मुक्तिधाम के समीप सब्जी व फल विक्रय के लिए स्थान दिया जा रहा है।कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

एफआईआर के निर्देश

कलेक्टर ने निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर में बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिन कॉलोनाइजर्स, भूमाफियाओं द्वारा जमीन के मामलों में गड़बड़ी की गई है, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे। इस दौरान कलेक्टर ने वर्धमान नगर कॉलोनाइजर द्वारा की गई गड़बड़ी पर उसके विरुद्ध एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए।

कृषि अधिकारियों का रूकेगा वेतन

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा शिकायतों के निपटान में धीमी गति पर सख्त नाराजगी जताई। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कृषि विभाग 30 वीं रैंक पर जबकि लीड बैंक 48 वीं रैंक पर है। कलेक्टर ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। सैलाना विकासखंड में एसडीएम सैलाना द्वारा की गई जांच के दौरान 23 कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर के अनुपस्थित पाए जाने पर कलेक्टर ने सभी की अनुपस्थिति दिवस की सैलरी काटने के निर्देश दिए।

पत्रिका 19-4-

स्वतंत्र एलान

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों का निरीक्षण

स्वतंत्र एलान 19.4.22

सफाई का कार्य नियमित रूप से करवाने व भुट्टा बाजार में लगी अवैध गुमटी को हटाने के दिये निर्देश

रतलाम । शहर के व्यावसायिक व अन्य क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कर व्यावसायिक क्षेत्र व मुख्य मार्गों की सफाई के साथ ही नाले नालियों की सफाई के निर्देष संबंधितों को देने के साथ ही भुट्टा बाजार में लगी अवैध गुमटी को हटाने के निर्देष भी दिये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दो बत्ती, सैलाना बस स्टैण्ड, गीता मंदिर रोड, भुट्टा बाजार, डालू मोदी बाजार, नाहरपुरा, चांदनी चौक, नौलाईपुरा, धानमण्डी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर नाले नालियों की सफाई के निर्देष संबंधित को देते हुए नौलाईपुरा क्षेत्र के नाले की सफाई का कार्य तत्काल प्रारंभ करवाने के निर्देष दिये।

निरीक्षण के दौरान उन्होने अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देष दिये कि शहर के सभी सार्वजनिक शौचालय व यूरिनल की नियमित रूप से सफाई करवाई जाये सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी इस हेतु सभी पुरी निश्ठा, लगन एवं ईमानदारी से कार्य करे। गंदगी, भवन निर्माण सामग्री फैलाकर अतिक्रमण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार अरूण अग्रवाल पर 3000, धर्मेन्द्र सिसोदिया पर 2000, धर्मेन्द्र टांक पर 1000, मनोहर सिंह, सुजानमल, राम किषन पर 500-500, हरि सिंह व नूर पर 250-250, रमेष, निर्मल व अनिल पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी व अतिक्रमण ना करने की समझाईष दी। निरीक्षण के दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा, श्री अनवर कुरेषी, राजस्व उप निरीक्षक श्री हरीष मिश्रा, झोन प्रभारी श्री विनय चौहान, श्री धर्मेन्द्र जोगाया के अलावा श्री कुलदीप भट्ट आदि उपस्थित थे।

स्वतंत्र एलान
19.4.22

नॉन स्लम के 2240 ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों में से 741 हितग्राहियों ने फ्लेट हेतु जमा कराए 6.40 करोड़

प्रसारण न्यूज • रतलाम 19-4

नॉन स्लम क्षेत्र के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित ईडब्ल्यूएस फ्लेट हेतु पूर्व में आमंत्रित आवेदनों में से पात्र पाये गये 2240 हितग्राहियों से हितग्राही अंशदान 3.50 लाख या हितग्राही अंषदान की 10 प्रतिशत पंजीयन राशि 35,000/- जमा कराये जाने हेतु 5 से 18 अप्रैल निर्धारित की गई थी, जिसके तहत 18 अप्रैल तक 121 हितग्राहियों ने हितग्राही का संपूर्ण अंशदान 3,50,000 करवाते हुए 4 करोड़ 23 लाख 50 हजार व 620 हितग्राहियों द्वारा हितग्राही अंशदान का 10 प्रतिषत 35,000 जमा करवाते हुए 2,17,00,000 की राशि जमा करवाई इस प्रकार कुल 6 करोड़ 40 लाख 50 हजार की राषि जमा कराई।

रात्रिकालिन सफाई के 2 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा- रतलाम। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा 17 अप्रैल रविवार को निरीक्षण किये जाने पर महेश-प्रभुदयाल व रघु-कन्हैया द्वारा अपने कर्त्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के निर्देश संबंधित को दिए।

18 अप्रैल सोमवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 252 ट्रीप

रतलाम। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है, जिसके तहत 18 अप्रैल सोमवार को 111 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया।

18 अप्रैल सोमवार को डम्पर से 29185 किलो, ट्रेक्टर से 13055 किलो, मैजिक सूखा कचरा 45785 किलो, मैजिक गीला कचरा 23860 किलो, सेनेटरी कचरा 3 किलो, घरेलू हानिकारक कचरा 3.1 किलो इस तरह कुल 111891.1 किलो कचरा जलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया। 19-4

नगरीय निकायों के लिए सरकार ने खोला खजा

931 करोड़ में होगा प्रदेश के निकायों

दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले को 432 करोड़ 50
मिलियन प्लस शहरों को 499 करोड़ रूपये की राशि अं

विनोद शर्मा, स्वतंत्र समय, भोपाल

मप्र के विकास के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए सरकार का खजाना खोला है। सोमवार को शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की सभी नगरीय निकायों को बड़ा तोहफ़ा दिया है। सीएम ने प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित 931 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की। इसमें चार मिलियन प्लस शहरों (दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले) को 432 करोड़ 50 लाख एवं नॉन मिलियन प्लस शहरों को 499 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है।

इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि मिलियन प्लस शहरों में पेयजल, स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए भी आज 301 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। भोपाल, इंदौर,ग्वालियर, जबलपुर के मित्रों से मेरा आग्रह है कि इस राशि का बेहतर उपयोग करते हुए निश्चित समय सीमा में कार्यों को पूर्ण करें।हमारे जिन शहरों की आबादी दस लाख से कम है, उनको भी दो अनुदान जारी किये गये हैं। पहले 500 करोड़ और अब 499 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस राशि का उपयोग निकाय विभिन्न विकास कार्यों एवं पेयजल तथा सॉलिड मैनेजमेंट आदि के लिए कर सकता है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि इस राशि से इन शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार, पेयजल योजनाओं, सीवरेज एवं स्वच्छता के कार्य तथा आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास के कार्य किये जा सकेंगे। मिलियन प्लस शहर वायु गुणवत्ता सुधार संबंधी कार्य के लिये 131 करोड़ 50 लाख रूपये और पेयजल, सीवरेज एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों में 301 करोड़ रूपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह नॉन मिलियन शहर 199 करोड़ 60

लाख रू
299 क
सीवरेज,
आदि क

अतिक्र
बनें

नगरी
भूपेन्द्र
स्वच्छता

...तो मैं समझूंगा दाल में कुछ काला है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों को राशि अंतरित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के हितग्राही को किस्त मिलने में विलंब नहीं होना चाहिए। विलंब होता है तो गड़बड़ी की संभावना बनती है। यदि ऐसा हुआ तो मैं समझूंगा कि दाल में कुछ काला है और हम भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शहरी विकास के काम तेजी से चल रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर को वायु की गुणवत्ता में सुधार, सिटी एक्शन प्लान के क्रियान्वयन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। पेयजल और स्वच्छता के लिए भी प्रविधान किया है। 10 लाख से कम आबादी शहरों को 499 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इस राशि का उपयोग वेतन-भत्ते को छोड़कर विकास कार्यों में किया जाना है। योजना बनाकर समयसीमा में लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम करें। पेयजल की आपूर्ति के काम को प्राथमिकता में करना है। स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है। इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हमें देश में नंबर एक पर रहना है। मानसून के पहले शहरी क्षेत्र की सड़कों के रखरखाव का काम पूरा कर लें। प्रधानमंत्री आवास के लिए पर्याप्त राशि है। समय से किस्त हितग्राही के खाते में जमा करें।

अवन्तिका/ 11/4/22